भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3577

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026

19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

विनिवेश और परिसंपत्ति का मुद्रीकरण

3577. श्री नवीन जिंदल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित विनिवेश लक्ष्य और वास्तव में प्राप्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का ब्यौरा क्या है जिनमें वर्ष 2026-27 में विनिवेश का प्रस्ताव है; और

(ग) राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के तहत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान संशोधित अनुमानों के अनुसार, विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंर्तगत 33,837 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी, जिसमें विभिन्न युक्तियों के माध्यम से इक्विटी निवेश और लोक परिसंपत्तियों का प्रबंधन करके मिलने वाली अनुमानित प्राप्तियां शामिल हैं। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 45,306.05 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है, जिसमें विनिवेश से 16,885.56 करोड़ रुपये और परिसंपत्ति के मुद्रीकरण से 28,420.49 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ख): वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान के लिए विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंर्तगत 80,000 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। भारत सरकार ने दिनांक 05.08.2026 की स्थिति के अनुसार 27,568.06 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रेलवे वित्त कार्पोरेशन लिमिटेड और कोच्ची शिपयार्ड लिमिटेड का बिक्री प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश करके और इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रणनीतिक विनिवेश करके 21,201.13 करोड़ रुपये जुटाना तथा परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करके 6,366.93 करोड़ रुपये जुटाना शामिल था। इसके अलावा, विनिवेश एक सतत् प्रक्रिया है और विशिष्ट लेन-देन का निष्पादन/पूरा होना बाजार की परिस्थितियों, घरेलू और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, भू-राजनीतिक कारकों, निवेशकों की रूचि तथा प्रशासनिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है और विनिवेश लेन-देन की बाजार-संवेदनशील प्रकृति के कारण विनिवेश के लिए समय-सीमा तय करना व्यावहारिक नहीं है।

(ग): राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 1.0 में **(**वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के दौरान**)** 6 लाख करोड़ रुपये की मुद्रीकरण क्षमता वाली परिसंपत्तियां शामिल थीं, जिसके संबंध में लगभग 5.3 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल किया गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा के अनुसार, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (एनएमपी 2.0) को दिनांक 23 फरवरी, 2026 को शुरू किया गया था। एनएमपी 2.0 ने वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2030 तक पांच साल की अवधि के दौरान 5.8 लाख करोड़ रुपये के निजी क्षेत्र के निवेश सहित 16.72 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया है। एनएमपी फलदायी लोक परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण को सक्षम बनाता है, जिससे नई परियोजनाओं और पूंजीगत व्यय में पुनर्निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं।

****